which has got the minimum wage since these wages were last revised ?

**श्री भागवत झा आजाद** : जहां तक सबसे अधिक वेतन का प्रश्न है वह केरल में है, वहां पर 4·50 पैसे मजदूरी है। हरियाणा में एक से दो रु० तक है....

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)**: सब से अधिक हरियाणा में है जहां पांच से सात रुपये मजदूरी है।

**श्री भागवत झा आजाद** : केरल में 4·50 पैसे मजदूरी है। केन्द्रीय सरकार ने जो नियत की है वह 2·50 पैसे से 3·70 पैसे तक है। दूसरा नम्बर पंजाब का है जहां ढाई रु० से तीन रु० भोजन के साथ मजदूरी दी जाती है, और तीन रु० से 3·50 पैसे बिना भोजन के। सबसे कम महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में ·62 पैसे से लेकर एक रु० तक है और तमिलनाडु में ·75 पैसे 1·25 पैसे है, वह भी सम्पूर्ण राज्य में नहीं है, कुछ भागों में है।

**श्री मोलह प्रसाद** : मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला स्तर पर खेत मजदूरों और खेत मालिकों के बीच में जो विवाद खड़े होते हैं, या कम मजदूरी मिलती है उसके सम्बन्ध में खेत मालिकों द्वारा पुलिस से मिल कर जो उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाये जाते हैं, उस के निराकरण के लिये जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी कोई नियुक्त करेंगे, या इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सुझाव देंगे ताकि खेतिहर मजदूरों पर होने वाले जुल्मों का निराकरण हो सके।

दूसरी बात यह है कि आधुनिक मशीनों का ज्यादा सहारा लेने के लिये कृषि मंत्रालय तत्पर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कृषि यंत्रों द्वारा जब खेती करायी जायगी तो खेतिहर मजदूर बेरोजगार होंगे अतः उनके लिये कोई वैकल्पिक रोजगार श्रम मंत्रालय ढूंढ रहा है ?

**श्री भागवत झा आजाद** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस काम को अपने उस राज्य को कहें जहां पर उनकी सरकार है। जैसा मैंने बार बार बताया कि संविधान के अन्दर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अपने सीमा अधिकार हैं...

इस सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन का निश्चय करना, समय समय पर उसमें संशोधन करना, उसका कार्यान्वय करना, यह तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तो उसका फिक्सेशन, दूसरा रिवीजन और तीसरा इनफोर्समेन्ट। यह तीनों चीजें राज्य सरकारों के अन्तर्गत हैं और इसके लिए समय समय पर हम उनको कहते हैं। विभिन्न कान्फ्रेंसों में उनसे बातचीत करते हैं व उनसे निवेदन करते हैं और जैसा कि श्री मोलह प्रसाद ने कहा हम उनसे कहते हैं कि वह न केवल निश्चय करें बल्कि उनके द्वारा उसका कार्यान्वय भी होना चाहिए।

जहां तक यह सवाल कि उनको रोजगार नहीं मिलता है जाहिर है कि देश में हम सभी को काम देना चाहते हैं। यह प्रश्न सिर्फ एक राज्य का नहीं अपितु विभिन्न राज्यों का है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें अपने अपने यहां उचित काम करती हैं।

## SHORT NOTICE QUESTIONS

### भाखड़ा में बिजली का उत्पादन

S.N.Q.26. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा में बिजली के उत्पादन की स्थिति चिन्ताजनक हो गई है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को बिजली की सप्लाई में काफी कटौती कर दी गई है ;

(ख) बिजली की यह कमी कितने समय तक रहेगी और इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) बिजली के औद्योगिक तथा कृषि उपभोक्ताओं को इसके कारण कितनी हानि होने की संभावना है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि बिजली की वर्तमान कमी मई, 1970 के अंत तक पूरी हो जाएगी जब नदी के अंतः प्रवाह में सुधार होने की संभावना है। सभी अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनों को जुटाया जा रहा है। बहरहाल, इस क्षेत्र में बिजली की सामान्य कमी को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों तथा केंद्रीय सरकार ने बहुत सी नई बिजली परियोजनाएं हाथ में ली हैं।

(ग) पंजाब तथा नांगल फर्टिलाइजर फैक्टरी ने अपने विद्युत भार को लगभग 25% कम कर दिया है। हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों ने भी इस प्रणाली पर अपने भारों को कम कर दिया है। बिजली के न मिलने से जितनी हानि औद्योगिक तथा कृष्य उपभोक्ताओं को होगी उसका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और वह इस बात पर भी निर्भर होगी कि कटौती किस प्रकार की जाती है और स्थिति का सामना करने के लिए कौन से वैकल्पिक प्रबंध किए जाते हैं।

**श्री जनेश्वर मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, पिछले 10–12 साल से इस सरकार की दो बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं जिसका बहुत बधावा बजा, एक तो पंचशील और दूसरे नम्बर पर यह भाखड़ा। पंचशील तो उड़ गया चीनी हमले के समय, भाखड़ा भी चटक गया था। अब की बार उसने 10–12 करोड़ लोगों की जिंदगी को खतरा पहुंचाया है। 20 अप्रैल को अखबार में छपा है कि गोविन्दसागर झील जहाँ से बिजली निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है वहाँ से जितना पानी निकलता है उसका तीस फीसदी कम पानी आता है। क्या सरकार पानी की इस कमी को किसी नदी से नहर जोड़ कर पूरा करने की कोशिश करेगी ?

दूसरा मेरा सवाल है कि इस सरकार ने 20 फीसदी बिजली की कटौती औद्योगिक उत्पादकों और कृषि उत्पादकों को की है। दो तरह के आदेश दिये हैं। नम्बर एक आदेश यह दिया है कि औद्योगिक उत्पादकों को, सिनेमागृह हफ्ते में पाँच दिन काम करें, नम्बर 2 आदेश दिया है आपने वहाँ के किसानों को, ट्यूबवैल वालों को कि तीन दिन तुम्हारी बिजली कटी रहेगी तो औद्योगिक उत्पादकों और कृषि उत्पादकों में यह एक दिन का फर्क क्यों किया गया है इसकी सफाई होनी चाहिए ? यह मैं तीन सवाल सरकार से करना चाहता हूं।

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao)**: The load on the Bhakra system has been going up very rapidly. For example, in Punjab alone, the load is now half a million K.W. and it will go up to 1 million in the course of the next four years. The Bhakra system is not able to cope up with the heavy amount of load built up in the northern region very rapidly in Punjab, Haryana and Rajasthan, which draw power from the Bhakra system. With regard to diversion of waters from Bohkra to Sutlej to make more power available, that is exactly the idea of the Beas-Sutlej project, on which we are now engaged. That is now under construction and it is expected to be commissioned towards the end of the fourth plan. With regard to the cut, the Punjab Government is seized of the matter and is arranging the cut in a way that is least harmful to society. I may also tell the hon. member that we are trying to reduce this cut in Punjab-tiself. For example, yesterday we got another machine on in Delhi and we have reduced the load of the Delhi system. Similarly, Rajasthan also is not rendering power from Bhakra by taking from Chambal. We have also arranged to stop supply of power to U. P. We are trying our best. The shortage will be there only for one month.

**श्री जनेश्वर मिश्र** : अध्यक्ष महोदय इन्होंने मेरे एक सवाल का जबाब नहीं दिया इसलिए अभी मैं दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा हूं। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि किसानों को हफ्ते में तीन दिन इन्होंने काट लिया, नलकूप की बिजली की कटौती कर दी जबकि औद्योगिक उत्पादकों को सिनेमागृहों को हफ्ते में दो दिन की छुट्टी है ऐसा फर्क इन्होंने क्यों किया है ?

**Dr. K. L. Rao** : I have already submitted that it is the State Government who have decided.

**श्री जनेश्वर मिश्र** : दूसरा सवाल यह है कि वहाँ पर जो लोग औद्योगिक सामान तैयार करते हैं और खेती का सामान तैयार करते हैं उन लोगों के सामने सब से बड़ा खतरा आया है कि देश में और विदेश के बाजार में भी जो वायदा अब तक किया हुआ है सामान देने का, जो सामान देने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं उनके रोजगार को नुकसान हो रहा है तो क्या सरकार वहाँ के किसानों को और छोटी औद्योगिक पैदावार करने वाले लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसका मुआविजा देने को तैयार है क्योंकि इनकी बिजली और इनके भाखड़ा बाँध की वजह से यह नुकसान हो रहा है ?

नम्बर 2 क्या सरकार यह बतायेगी कि वह कौन से इंजीनियर और मंत्रालय के बड़े अफसर थे जिनका गणित फेल होने से यह बहुत बड़ा

खतरा भाखड़ा बांध पर आया है तो क्या उनको सजा देंगे या देश में जो बहुत बधावा बजा है उसके लिए पछतावा करके देश की जनता से माफी मागेंगे ?

**Dr. K. L. Rao** : This cut is purely temporary and there is no question of a parmanent cut. The river Sutlej has low flows in the months of March and April, and we knew it perfectly. The load on the Bhakra system has grown so much that Bhakra alone is not able to solve the problem. Therefore, in the lean period of March and April—it may happen next year also—there is bound to be cut unless we put some other unit. We are hoping that we will be able to generate more power at Delhi. As regards compensation I do not think there is any compensation admissible because hydel power is subject to variation.

**श्री रणधीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या यह हकीकत है कि भाखड़ा से जो बिजली दी जाती है किसानों से उसका ज्यादा रेट लिया जाता है और इंडस्ट्रियलिट्स से उस बिजली का थोड़ा रेट लिया जाता है ?

क्या यह सही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इंडस्ट्रीज चलाने के लिए रेगुलर बिजली मिलती है जबकि किसानों को मिलने वाली बिजली का ब्रेकडाउन होता रहता है अकसर वह फेल होती रहती है ?

क्या यह भी सही नहीं है कि दिल्ली में वह बिजली भाखड़ा वाली 2 पैसे फी यूनिट के हिसाब से दी जाती है और दिल्ली वाले उसी बिजली को यू०पी० में 5 पैसे फी यूनिट दे रहे हैं? क्या यह सही नहीं है कि हरियाणा का जो हक है बिजली का भाखड़ा में वह उनको नहीं मिल रहा है और वह हक उन्हें दिलाने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

**Dr. K. L. Rao** : In regard to Harayana it is entitled to 33 per cent power from Bhakra System. But it is not taking up all this power because Haryana is getting power from Delhi and Faridabad. With regard to rate, I do not think 2 paise is correct. It is more than 4 paise. It depends on the agreement between the various parties which are in the Bhakra system.

**Shri Shri Chand Goyal** : Sir, this is an important question and I would ask a few pertinent questions from the hon. Minister. First, you have said that the load on Bhakra is rather great. Now, in order to relieve this load you were to construct this power house at Dehar.

The time schedule for the construction of this power house was by 1971-72. I would like to be assured whether you will be able to stick to the revised schedule, that is, completion of the Dehar power house by 1973-74, because by the construction of that power house you will be able to work four new machines which will supply more electric power.

Secondly, have you already constructed the transmission linses ? My information is that the transmission lines will not only transmit the electric power which will be created by the Dehar power house but this power house will also release a large amount of water which will be put in the Sutlej thereby enabling you to work all the ten machines. Therefore, have you started the construction of these transmission lines so that when the Dehar power house is ready you shall be in a position to transmit all the electric power that will be produced ?

Thirdly, I would like to know whether you will be able to stick to the time schedule of the new projects of Siul, Salal and Kissau Dam which are to produce the necessary electric power for the northern region.

Then, the Beas Control Board has no engineer who can be called a power engineer. These projects are suffering because there are only irrigation engineers. Has the hon. Minister, being an irrigation engineer, fancy only for irrigation engineers ? He is not posting any power engineers there. These projects are mixed, power and irrigation, projects ; 70 per cent is power and, 30 per cent is irrigation. But, unfortunately the Chairman of the Board, the Secretary and all the engineers are irrgiation engineers and none of them is a power engineer. Therefore the development of these projects is suffering. I would like to know whether he would change the complexion of these boards and give adequate representation to power engineers.

Lastly, I would like to know whether in order to secure the best expertise and to convert the regional electricity board for the northern region of Jammu and Kashmir,

Himachal, Punjab and Haryana, into an executive body to end inter-State disputes, you are considering the finlisation at an early date of the regional electricity board scheme.

**Dr. K. L. Rao** : With regard to the Beas-Sutlej project the hon. Member is quite correct that it forms a very important part of Power Supply for the northern region. Our ambition is to see that Beas project is expedited as much as possible. Unfortunately, these projects have gone up very much in costs and, therefore, are facing a bit of trouble. Any way, we are hoping to complete this project by 1973-74. It may be a few months this way or that but we are trying to stick to the target.

Then, about the transmission lines, it does not take more than two years to construct them. As I have already submitted, because of the financial strain we are trying to use whatever finances we have for the construction of the Beas-Sutlej project and the Pong Dam. We have already constructed some transmission lines and will complete them as early as possible.

**Shri Shri Chand Goyal** : He is misinforming the House when he says that it will take two years. It will take 7 to 8 years to construct the transmissin lines. Afterwards he will say that they do not have the transmission lines.

**Mr. Speaker** : Please do not interrupt the Minister. He is the only Minister who is so confident in his replies.

**Dr. Ram Subhag Singh** : Does it mean that others are not ?

**Mr. Speaker** : I am sorry. What I meant was that he is all the time very much unperturbed. The only thing about him is that he never refuses a short notice question and that is my headache.

**Dr. K. L. Rao** : What I was submitting was that the generation of power takes longer time than the transmission lines. We are carefully planning it and you can rest assured about it.

I can assure the hon. Members we will definitely see that the transmission lines are put in time. We never allow transmission lines to lag behind.

As regards the Salal and Siul projects to which the hon. Member referred, we will strick to the time-schedule.

About the other question of the Beas Construction Board, power engineers and so on, what we do is, in these big projects, in the first stage, when the civil engineering works are more, we employ civil staff and, when power system begins to be implemented, we employ the power wing. Only yesterday, we decided to have the power engineering service and to have a Chief Engineer for power. Otherwise, if we employ power engineers in the very beginning of the project, it will be a waste of money.

About the Regional Electricity Board, we have already got the Regional Electricity Board in the northern range. It is functioning. Each State takes up its chairmanship by rotation. At present, the Jammu and Kashmir Minister is the Chairman of the Board.

**श्री गुरचरण सिंह** : मिनिस्टर साहब ने बतलाया और चर्चा भी है कि पंजाब में बिजली की बड़ी कमी है और कमी की वजह से दिल्ली वालों और इंडस्ट्री के लिये वह 3 दिन बन्द रहती है। एक तरफ तो बिजली की कमी है और दूसरी तरफ रोज मिनिस्टरों के बयान निकलते हैं कि 100 गाँवों को बिजली दी जायेगी, 200 गाँवों को बिजली दी जायेगी और जिन लोगों के पास कनेक्शन हैं उनके साथ मजाक हो रहा है। पंजाब में जो जमीदार हैं चाहे वह बिजली एक दिन इस्तेमाल करें या ज्यादा, क्योंकि आपने खुद ही तीन दिन की कमी की है, फ्लैट रेट उनसे वसूल हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक इस कमी को दूर नहीं किया जाता क्या सरकार पंजाब गवर्नमेन्ट को इससे रोकेगी और कहेगी कि लोगों से मजाक न किया जाये, साथ ही आगे और लोगों को बिजली न दी जाये और लोगों की मोटरें न चलें ? इस कमी को दूर करने के लिये क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट भटिंडा थर्मल प्लान्ट को स्पीड अप करने के लिये कुछ कर रही है ?

**Dr. K. L. Rao** : We can evercome the present shortage. But the main trouble is there are so many applications for electricity. I do not know whether the hon. Member wants us to stop taking immediately any additional load. If that is the desire of the hon. Member, we can do that. Unfortunately, the demand for power is so much

that we are not able to refuse the demand. We are trying to meet it somehow or other. For example, the Punjab Government now, in order to meet the rural power utilisation and to make up the shortage in the villages, have suggested to take some diesel sets. The main point is, today, whatever demand is there, we try to meet but the demand is going up everyday. The demand of half a million K.W. of power of Punjab is going to be 1 million Kw. in the next few years.

**श्री ओंकारलाल बोहरा** : राजस्थान को चम्बल परियोजना से बिजली मिलती है, उस से और जिस इलाके में भाखरा बांध पड़ता है उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राजस्थान के साथ जो ऐग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से जितनी-बिजली उस इलाके को मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल रही है। वह डेजर्ट-एरिया है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि भांखरा परियोजना से राजस्थान को निअर फ्यूचर में अधिक से अधिक कितनी बिजली और कितना पानी मिलेगा क्योंकि राजस्थान कैनाल न बनने से सारा एरिया अधूरा पड़ा हुआ है। राजस्थान कैनाल के अभाव में भाखरा बांध से हमको सरकार क्या विशेष मदद करने जा रही है ?

**Dr. K. L. Rao** : The allocation between Punjab and Rajasthan is very clear. Only between Punjab and Haryana it is not settled. So far as Rajasthan is concerned, there is a very definite allocation of water and power. From the Bhakra system, Rajasthan gets 15.2 per cent. It is all fixed : it cannot be altered. From the extra water that we are going to get from the Indus, out of 15.85 million acres ft., Rajasthan gets 8 million acres ft. of water. The only question is about allocation between Punjab and Haryana. We are trying to settle it. So far as Rajasthan is concerned, the allocation is clear and is fixed.

**Dr. Sushila Nayar** : I would like to know from the hon. Minister whether the calculations of power supply made at the beginning have been belied in the light of experience and whether the silting that he referred to a moment ago is much more than what was anticipated. I am told that due to the cutting down of forests higher up on the Himalayan slopes, a lot of soil is washed down by rains which is causing silting of Bhakra at an alarming rate. If this be so, I would like to know from the hon. Minister what precautions, if any, and what remedial steps, if any, have been taken in this respect so that this project fulfils the expecatations with which it was undertaken.

**Mr. Speaker** : This is a very simple question and it has taken a lot of time by questions and replies. I am feeling rather helpless.

**Dr. Sushila Nayar** : The problem of silting is very relevant, Sir. What is there irrelevant—I cannot understand. This is a very relevant question. What was the calculation of anticipated power production?

**Mr. Speaker** : So far as you are concerned, it is relevant. But I am asking him.

**Dr. K. L. Rao** : The hon. Member is correct in drawing attention to the fact that the Bhakra reservoir is being silted up. But it is not at an alarming rate. Originally we thought that there servoir will get silted up in 500 years. We now find that it will get silted up in 350 years. 350 years itself is a long period. Compared to other reservoirs in the country like D. V. C., this reservoir is not getting silted up at all at an alarming rate.

**Shri Randhir Singh** : In another 50 years there will be no dam.

**Dr. K. L. Rao** : In view of the fact that this is an important reservoir and the flooding of the head-works and the entire area, we are going to build another dam higher up in order to reduce the silting in the reservoir. We are also taking up soil conservation measures that are necessary in this regard.

**Dr. Sushila Nayar** : He did not reply to my question. What was the expected generation and to what extent is it falling short.

**Dr. K. L. Rao** : That is not affected at all.

**श्री कंवर लाल गुप्त** : भाखड़ा नंगल से दिल्ली को भी बिजली मिलती है। दिल्ली को दी जाने वाली बिजली कम करने के बारे में भी कई बार थ्रेट्स दिये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिल्ली वालों को एश्योरेंस देगी कि दिल्ली को जितनी बिजली

दी जाती है, वह दी जाती रहेगी और जो कमी पड़ेगी उसको भी पूरा कर दिया जाएगा ?

**Dr. K. L. Rao** : The Delhi Bhakra power is fixed at 1.2 million kilowatts. That is not being altered. The only point at this moment is that whenever there is shortage we must adjust, and that we are trying to do. We are commissioning every unit that we have got in Delhi. Whatever help we can render to the system in the next few months we must do. It is in that way we are working. So far as sharing of Bhakra power is concerned, there is no difficulty for Delhi.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**खेतिहर मजदूरों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किया गया अध्ययन**

*1326. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता लगा है कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम को खेतिहर मजदूरों पर भी लागू करेगी ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) और (ख). जी नहीं । फिर भी राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 28·27 में व्यक्त किया है कि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कृषि रोजगार के बड़े क्षेत्रों को अधिनियम की सीमा के अन्दर नहीं लाए हैं। यह मामला पहले ही संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

NEED BASED WAGE FOR CHANDIGARH

*1327. **Shri Shri Chand Goyal** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have worked out the need-based wage for the Union Territory of Chandigarh ;

(b) if so, the estimated number of Government employees and semi-Government employees in Chandigarh whose wages are below the need-based wage ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to secure the need based wage in the Union Territory of Chandigarh ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)**. (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The structure of emoluments etc. of employees of Union Territories has been referred to the Third Pay Commission, set up by the Government of India.

FINANCIAL AID TO SMALL NEWSPAPERS

*1328. **Shri D. Amat** :

**Shri N. Shivappa** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved the modified plan for financial aid to small newspapers which has been examined by his Ministry in consultation with the Ministry of Finance ;

(b) if so, the salient features of this plan ; and

(c) the steps being taken to implement it ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting ; and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) to (c). A proposal to set up a Newspaper Finance Corporation to give financial aid to small and medium newspapers in the country, is under active consideration. It is not possible to indicate, at this stage, the salient features of the plan.

INDIAN NEWSPAPERS GETTING FOREIGN ASSISTANCE

*1329. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Informationand Broadcasting and Communications** be pleased to state :